

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

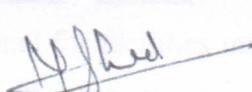
सरकारी मोहर

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मॉग का पूर्ण औचित्य

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली-खमारी-
थापला-जलालगांव से देचौरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

मंगोली से जलालगांव तक पूर्व में मोटर मार्ग निर्मित है। जिसमें वाहनों का आवागमन बना हुआ है। जलालगांव से देचौरी तक वर्तमान में कोई मार्ग आवागमन हेतु निर्मित नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु जलालगांव से देचौरी तक 7.0 किमी० लम्बाई में मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 883/111(2)/08-66 (एम०एल०ए०)/07 दिनांक 28.03.2008 द्वारा रू० 245.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उक्त मार्ग के निर्माण के पश्चात् ग्रामीणों को 5.0 किमी० कम दूरी तय करनी पडेगी। उक्त मार्ग के निर्माण में 6.05 किमी० लम्बाई व 9.0 मी० चौड़ाई में आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि मार्ग निर्माण हेतु उपलब्ध नहीं है। जैसा कि पृष्ठ सं० (12A) में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में भी अंकित किया गया है। प्रस्तावित संमरेखण में वृक्षों का पातन भी कम होगा तथा आरक्षित वन भूमि भी कम उपयोग होगी। इन्ही कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्ग के निर्माण हेतु 6.05 किमी० लम्बाई व 9.0 मी० चौड़ाई में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।


अपर सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
नैनीताल


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
नैनीताल


अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
नैनीताल

24
पत्र - 30

(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Nainital

No:-

Dated 20.11.14

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 5.445 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.D., P.W.D, Nainital for **Construction of Mangoli Khamari Thapla Jalalgaon Dechauri Motor Road** in Nainital district falls within jurisdiction of **Jalalgaon** village (s) in **Nainital** tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.445 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23.4 to _____ annexure _____
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
नैनीताल


जिला सहायक इन्चार्ज अधिकारी
नैनीताल


जिला सहायक इन्चार्ज अधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

No---

Dated-----

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली-खमारी -थापला-जलालगौव से देचोरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

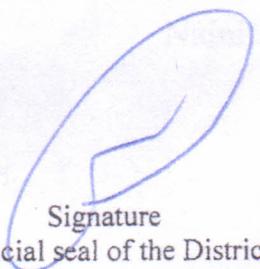
To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

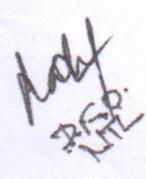
In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 5.445 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.D.P.W.D Nainital for Construction of Mangoli Khamari Thapla Jalalgaon Dechauri Motor Road for Road Work (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Jalalgaon village (s) in Nainital tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.445 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Nainital villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communitis, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA


Enc: As above. अधिकारी
देचोवाव


Signature
(Full name and official seal of the District Collector)


R.S.D.
LTL

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR

DISTRICT NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule 1 of the Forest Rights Act (FRA), 2006 & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr Deepak Rawat I.A.S district collector, Nainital on dated 20.11.14 at time 11.30 AM at Nainital in which application claiming rights in Kotabag Tehsil area measuring 5.445 hect for the construction of Mangoli hamari Thapla Jalalgaon to Dechauri in District Nainital under state sector forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Kotabag Tehsil sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place... Nainital
Date... 20.11.14

District Collector-cum-Chairman
District Level Committee
Nainital

विद्या समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

[Signature]
प्रशासनिक कल्याण अधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

9/2/2014 - 30.2

संयोजना का नाम- संगोली-रकबाई-थापला-उल्लाखगाव देवोरी भोरा परिक्षेत्र

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति भा.मि.व.म.
उपखण्ड संगोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भोरा परिक्षेत्र
जिलाधिकारी देवोरी (43220) हे0 आरक्षित वन भूमि.....हे0
सिविल एवं सोसल वनभूमि, वन पंचायत भूमि: 1125 हे0 अर्थात कुल: 5445 हे0 वन भूमि) का
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील संगोली.....) की दिनांक 18/11/14 को
समन्वय बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डॉ. अ. क. शर्मा उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री अ. क. शर्मा उपजिलाधिकारी..... अध्यक्ष
2. श्री म. व. शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी..... अध्यक्ष
3. श्री मु. शर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी भोरा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
4. श्री ड. शर्मा बी.डी.सी क्षेत्र जिला सदस्य देवोरी

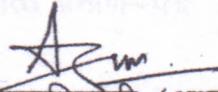
उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को संबोधित किया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत संगोली उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष आया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वनभूमि पर लम्बित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक स्थान हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अनुसूचित वनवासी एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। अतः प्रकरण के उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी

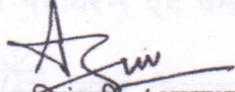
बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत संगोली उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

कमरा: 2पर

विद्योजना के निर्माण हेतु 5.145 हे० वनभूमि प्रयोक्ता एजेंसी
जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति
प्राप्त की गयी।


उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील-
जनपद- नैनीताल

जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील-
जनपद- नैनीताल।

प्राकृत - 303

परियोजना का नाम :- मंगोली - खमारी - थापला - जलालगाँव - डेवोरी मोर (iv)

सर्व का नक्काशा

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - जलाल गाँव
हसील नैनीताल, जिला नैनीताल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मंगोली खमारी थापला जलालगाँव डेवोरी निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (4.32 हे० आरक्षित वन भूमि, सिविल वन भूमि हे०, वन पंचायत भूमि 1.25 हे०) अर्थात् कुल 5.445 हे० वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जलालगाँव द्वारा दिनांक 19-10-2014 सम्मन ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों को सूचित किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु उक्त वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्तावित किया गया कि ग्राम जलालगाँव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 5.445 हे० पर ऐजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

गणेश सिंह महारा
ग्राम प्रधान
जलालगाँव

ह०/-



यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है तो सरकार उक्त विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र पर ग्रामवासियों के द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

गणेश सिंह महारा
सदस्य जिला पंचायत
ज्योलीकोट (नैनीताल)

Cost Benefit Ratio Chart

Name of Project – Construction of Motor Road from Mangoli Khamari Thapla
Khatigam to Dechori .

Block :- Kotabagh

District :-Nainital

No.	Particulars	Amount (Lac Rs.)	Remark
1	Total cost (Investment incurred)		
(A)	Construction Cost of Project		Rs 24500000.00
(B)	N.P.V. Amount to be deposited @ 9.20 Lac/Hectare	Rs. 3065535.00	
(C)	Substitute/Alternation Planlation Cost to be Deposited :-	700000.00	
	Total	3765535.00	24500000.00
2	Benefits:- Benefits from (Taking Age of Road As 50 Years)		
(A)	Economic Benefits- Taking Market Development	Rs.500.00	
(B)	Direct Employment of Labours-	Rs. 50.00	
(C)	Employment Generation Due to other activities	Rs. 70.00	
3	Therefore construction is Economically Viable and socially benfcial.		

[Signature]
 सहायक अभियन्ता
 ग्रामीय खण्ड, लो० नि० वि०
 नैनीताल

[Signature]
 अधिशासी अभियन्ता
 राष्ट्रीय राजमार्ग, लो० नि० वि०
 नैनीताल

22

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

No—

Dated-----

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली-खमारी -थापला-जलालगॉव से देचोरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

To WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 5.445 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.D.P.W.D Nainital for Construction of Mangoli Khamari Thapla Jalalgaon Dechauri Motor Road for Road Work (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Jalalgaon village (s) in Nainital tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.445 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Nainital villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

[Handwritten signature]
...कार
...

[Handwritten signature]

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

[Handwritten signature]
P.O.
Nainital